

## INDIAN M&E TO TOUCH US\$ 70 BN

I&B minister stated that the Indian M&E sector is estimated to reach the target of US \$70 billion by the year 2030

Speaking at the CII Dakshin South India Media & Entertainment Summit -2023 in Chennai, Thakur stated, "The media and entertainment sector in India is at an inflection point and as the industry's partner and facilitator, the Information & Broadcasting Ministry continues to undertake efforts to grow the sector to reach the target of US \$70 billion by the year 2030 from its current size of US \$30 billion as of today.

The Films Division of India, Directorate of Film Festivals, National Film Archive Of India, Children Film Society, India – under the umbrella of National Film Development Corporation of India (NFDC), will build better convergence and resource utilisation.

The government plans to invite filmmakers from across the world to come to India and collaborate with Indian filmmakers and work together for India to become the content hub of the world.

## BALANCE BETWEEN THE CONSUMER AND SERVICE PROVIDER

The Govt is seeking to smoothen things out in all the sectors. This was evident when Anil Bhardwaj, Director General, TCSR & Advisor (Broadcasting), TRAI, spelt out the regulator's role is consumer welfare and striking a balance between the interests of the service provider and the consumer at the FICCI Frames 2023 convention.

Bhardwaj highlighted balance industry growth, consumer welfare, and other intersectional concerns such as privacy, security and quality of service

Rahul Vatts, Chief Regulatory Officer, Airtel felt that the biggest stakeholders are the customers or the consumers as they are the focal point of that end who should get the best deal.

Mihir Rale, Chief Regional Counsel, Disney Star India said that the aim is that the media and entertainment



## 70 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचेगा भारतीय एमएंडई

आईएंडबी मंत्री ने कहा है कि भारतीय एमएंडई क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने का अनुमान है।

चेन्नई में सीआईआई दक्षिण साउथ इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट 2023 में बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि 'भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र एक मोड़ पर है और उद्योग के भागीदार और सुविधाकर्ता के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। आज के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा आकार से वर्ष 2030 तक 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस क्षेत्र का विकास करना होगा।

भारत का फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह, वाल फिल्म सोसाइटी, भारत-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की छत्रछाया में बेहतर कन्वर्जंस और संसाधन उपयोग का निर्माण करेगा।

सरकार दुनियाभर में फिल्म निर्माताओं को भारत आने और भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग करने और भारत को दुनिया कंटेंट हब बनाने के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रही है।

## उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के बीच संतुलन

सरकार सभी क्षेत्रों में चीजों को सुचारू करने की कोशिश कर रही है। यह तब स्पष्ट हो गया। यह तब स्पष्ट हो गया जबकि टीसीएसआर के महानिदेशक अनिल भारद्वाज और ट्राई के सलाहकार (प्रसारण) ने फिक्की फ्रेम्स 2023 सम्मेलन में नियामक की भूमिका

उपभोक्ता कल्याण और सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के हितों के बीच संतुलन बनाने की बात बतायी। श्री भारद्वाज ने संतुलित उद्योग विकास, उपभोक्ता कल्याण और गोपनीयता, सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता जैसी अन्य अंतःविषय चिंताओं पर प्रकाश डाला।

एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स ने महसूस किया कि सबसे बड़े हितधारक ग्राहक या उपभोक्ता हैं क्योंकि वे उस छोर के केंद्रबिंदु हैं जिन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलना चाहिए।

डिज्नी स्टार इंडिया के मुख्य क्षेत्रीय सलाहकार मिहिर राले ने बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी



ecosystem must contribute more to the GDP within constitutional frameworks.

## 11 MSOS LOOSE REGISTRATION

The Govt has cracked the whip on MSOs who have not complied with the framework laid down.

They cancelled the registration of 11 multi-system operators (MSOs) between April 12, 2023 and April 31, 2023. The total number of registered MSOs stands at 1,736 as of April 31, 2023 as compared to 1,747 on April 12, 2023.

The registration request for MSO Sasmita Network was rejected on April 20, 2023 due to suppression of vital information. Meanwhile, DEB TV's registration has been cancelled due to violation of Rule 10A of the Cable Television Networks Rules, 1994 and terms and conditions. Registration is cancelled on 26.04.2023. Bongaon Cable TV Network's registration has been cancelled due to violation of Rule 10A of the Cable Television Networks Rules, 1994 and terms and condition.



त्रं को सवैधानिक ढांचे के भीतर जीडीपी में अधिक योगदान देना चाहिए।

## 11 एमएसओ के पंजीकरण रद्द

सरकार ने निर्धारित ढांचे का पालन नहीं करने वाले एमएसओ पर शिकंजा कसा है। उन्होंने 12 अप्रैल 2023 और 31 अप्रैल 2023 के बीच 11 मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पंजीकृत एमएसओ की कुल संख्या 12 अप्रैल 2023 को 1747 की तुलना में 31 अप्रैल 2023 तक 1736 थी।

एमएसओ ससिता नेटवर्क के पंजीकरण अनुरोध को 20 अप्रैल 2023 को महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने के कारण खारिज कर दिया गया था। इस बीच केवल टेलीविजन नियम 1994 के नियम 10ए और नियम व शर्तों के उल्लंघन के कारण डीईवी टीवी का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पंजीकरण दिनांक 26.04.2023 को निरस्त किया गया। बंगानाव केवल टेलीविजन नेटवर्क का पंजीकरण केवल टेलीविजन नियम 1994 के नियम 10ए और नियम व शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया है।

## सी बैंड की समीक्षा

सी बैंड फ्रीक्वेंसी, जो असहमति का कारण रही है, समीक्षा के लिए तैयार है और सरकार 5जी और 6जी उपयोग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के सी बैंड को आरक्षित करने की योजना बना रही है। यह आईबीडीएफ द्वारा सरकार से सीबैंड (3700-4200 मेगाहर्ट्ज) में स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने की आग्रह के बाद आया है, क्योंकि इसका उपयोग प्रसारण सेवाओं के लिए भी किया जाता है।

महासंघ के अनुसार इस बैंड को अन्य सेवाओं के लिए आवंटित करने से प्रसारण क्षेत्र परेशान होगा क्योंकि सैटेलाइट सिग्नलों के साथ टेरिस्ट्रियल प्रसारण के हस्तक्षेप की संभावना है।

## REVIEW OF C BAND

C Band frequency, which has been a cause of disagreement, has been up for review and government plans to reserve the C-Band of radio frequencies for 5G and 6G use. This comes after IBDF urged the government not to auction spectrum in the C-band (3,700-4,200 MHz) as it is also used for broadcasting services.

According to the federation, allocating this band for other services would disturb the broadcasting sector because of the possibility of interference of terrestrial transmissions with the satellite signals.

## SHAMSHER SINGH TO LAUNCH NEWS CHANNEL

Popular TV journalist Shamsher Singh is set to launch a news channel with the backing of a corporate house.

Shamsher Singh was the Managing Editor of Zee Media's Hindi news channel 'Zee Hindustan'. His earlier stint was with Republic Bharat, India TV and India News.



SHAMSHER SINGH

## न्यूज चैनल लॉन्च करेंगे शमशेर सिंह

लोकप्रिय टीवी पत्रकार शमशेर सिंह एक कॉर्पोरेट घराने के समर्थन से एक समाचार चैनल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।

शमशेर सिंह जी मीडिया के हिंदी न्यूज चैनल 'जी हिंदुस्तान' के मैनेजिंग एडिटर थे। इससे पहले वे रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी और इंडिया न्यूज के साथ भी काम कर चुके हैं।